किसान हित में काम कर रहा केंद्रीय कृषि विकास संस्थानः सीबी पाण्डेय

लखनऊ (अमर भारती)। केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों की आय दोगुनी करने और खेती किसानी को रोजगार परक और उद्योगों से जोड़ने के लिए केंद्रीय कृषि विकास संस्थान अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। इसके तहत किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण तथा पंजीकृत कृषकों को अनुदानयुक्त ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। संस्थान के निदेशक चन्द्र भूषण पाण्डेय ने बताया कि केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संचालित योजनाओं में कृषक अपना निःशुल्क पंजीकरण कर योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा पूर्व में जारी नियुक्ति विज्ञापनों की परीक्षा इसी वित्तीय वर्ष में संपन्न कराया जाएगा जिससे बेरोजगारी दर में कमी आएगी। इसके साथ ही संस्थान के अधीन 1.5 लाख नौकरियों में चयन प्रक्रिया गतिशील है। वर्ष 2028-29 तक 3.5 करोड़ पंजीकृत कृषक परिवारों को डीबीडी के माध्यम से विभिन्न

● संस्थान के अधीन 1.5 लाख नौकरियों में चयन प्रक्रिया जारी

योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डेयरी उत्पादन, पशुपालन व औषधीय फसलों की खेती से अथवा कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों से किसानी को रोजगार परक बनाकर न केवल उनकी आय दोगुनी की जा सकती है बल्कि ग्रामीण परिवेश में विकास को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है।

पाण्डेय ने बताया कि केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा कोरोना काल के दौरान पलायित मजदूरों अथवा कृषकों के निःशुल्क पंजीकरण के पूर्व में जारी सैद्धांतिक सहमति को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जिससे सम्बन्धित कार्यशाला अथवा सेमिनार नवम्बर अथवा दिसम्बर में की जायेंगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के आधिकारिक वेबसाइट में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

किसान हित में केंद्रीय कृषि विकास संस्थान कर रहा कई योजनाएं संचालित

चर्चित राजनीति। ब्यूरो

लखनऊ। केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों की आय दोगुनी करने और खेती किसानी को रोजगार परक और उद्योगों से जोड़ने के लिए केंद्रीय कृषि विकास संस्थान अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। इसके तहत किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण तथा पंजीकृत कृषकों को अनुदानयुक्त ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। संस्थान के निदेशक चन्द्र भूषण पाण्डेय ने बताया कि केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संचालित योजनाओं में कृषक अपना निःशुल्क पंजीकरण कर योजनाओं का सीधे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा पूर्व में जारी नियुक्ति विज्ञापनों की परीक्षा इसी वित्तीय वर्ष में संपन्न कराया जायेगा जिससे बेरोजगारी दर में कमी आएगी। इसके साथ ही संस्थान के अधीन 1.5 लाख नौकरियों में चयन प्रक्रिया गतिशील है। वर्ष 2028-29 तक 3.5 करोड़ पंजीकृत कृषक परिवारों को डीबीडी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डेयरी उत्पादन, पशुपालन व औषधीय फसलों की खेती से अथवा कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों से किसानी को रोजगार परक बनाकर न केवल उनकी आय दोगुनी की जा सकती है बल्कि ग्रामीण परिवेश में विकास को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। पाण्डेय ने बताया कि केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा कोरोना काल के दौरान पलायित मजदूरों अथवा कृषकों के निःशुल्क पंजीकरण के पूर्व में जारी सैद्धांतिक सहमति को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जिससे सम्बन्धित कार्यशाला अथवा सेमिनार नवम्बर अथवा दिसम्बर में की जायेंगी। श्री पाण्डेय ने बताया कि केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के आधिकारिक वेबसाइट में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

16/10/22

अमर उजाला

प्रदेश

सीएजीडीआई में भर्ती प्रक्रिया शुरू

लखनऊ। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान (सीएजीडीआई) ने लंबित नियुक्तियों की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है। चार चरणों में संपन्न होने वाली प्रक्रिया का पहला चरण 15 से 25 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। संस्थान के निदेशक चंद्रभूषण पांडे ने बताया कि संस्थान के रिक्त पदों पर भर्ती आंशिक साक्षात्कार, लिखित परीक्षा और तकनीकी परीक्षा के माध्यम से चार चरणों में की जानी प्रस्तावित है। 15 से 25 अक्टूबर तक चल रहे प्रथम चरण के लिए केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय में परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। इस चरण का परिणाम 11 नवंबर को घोषित किया जाएगा। संस्थान के दैनिक ऑडिट के लिए मौर्या एंड मौर्या मैनेजमेंट सर्विसेज को 11 माह के लिए नामित किया गया है। ब्यूरो

सचिव की निगरानी में ग्राम पंचायतों की सफाई और फॉगिंग कराई गई। इस बार पुष्टि के लिए पांच-पांच गांव में किए गए कार्यों की फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर मांगी गई, जो विभाग के पोर्टल पर अपलोड की गई।

सीएजीडीआई में भर्ती परीक्षा शुरू

लखनऊ। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान (सीएजीडीआई) में कोविड काल व इससे पहले से रिक्त पड़े पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चार चरणों में संपन्न होने वाली इस प्रक्रिया का पहला चरण शनिवार को सम्पन्न हुआ। संस्थान के निदेशक चंद्र भूषण पांडे ने बताया कि संस्थान के रिक्त पदो पर भर्ती आंशिक साक्षात्कार, लिखित परीक्षा व तकनीकी परीक्षा के माध्यम से चार चरणों में की जाएगी। शनिवार से 25 अक्टूबर तक चल रहे प्रथम चरण के लिए केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के राज्य मुख्यालय में परीक्षा संपन्न कराई जा रही है।

एनआरएलएम कर्मी सुनवाई न होने पर रिमूव

लखनऊ। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का कार्य बहिष्कार एक माह से जारी है। मांगों पर सुनवाई न होने के कारण विभाग के सभी काम ठप हैं। वहीं, अब लामबंद कर्मी मिशन स्टेट व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव हो गए हैं। उनकी मांगे वेतन बढ़ोतरी, भत्ता बढ़ाना, रिक्त पदों पर भर्तियां करना समेत कई मांग हैं, जो प्रदेशस्तरीय बहिष्कार से निस्तारित

मुख्यमंत्री योगी के कुशल दिशा निर्देशन में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के ढाँचागत विकास की तैयारी

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ। औषधीय कृषि उत्पादों से लेकर दुग्ध उत्पादन तथा पारंपरिक कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों तक पहुंचाने के लिये जिस एकीकृत कार्ययोजना की प्रतीक्षा आजादी के बाद से ही की जा रही उसका प्रारूप अब उत्तर प्रदेश में व्यावहारिक धरातल पर दिखाई देगा। राज्य के लाखों शिक्षित ग्रामीण युवाओं को सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने के लिये केंद्रीय कृषि विकास संस्थान ने जो ढाँचागत योजना तैयार की है उसे योगी सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है।इसके साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों शिक्षित ग्रामीण युवाओं को सरकारी क्षेत्र में स्थायी रोजगार गारंटी देने की अभूतपूर्व योजना का भी शुभारंभ हो गया है।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के निदेशक सीबी पाँडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

दिशानिर्देशन में तैयार इस योजना के माध्यम से पूरे देश के 3 करोड़ 50लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किये जाने का दूरगामी लक्ष्य है जिसे 2028-29 के वित्तीय वर्ष तक पूरा कर लिया जाना निर्धारित है।इसी कार्ययोजना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 8169 कार्यनिष्पादन केंद्रों की अवस्थापना गत वित्तीय वर्ष 2021-22 तक पूरी कर ली गयी है और अब राज्य के 75जिलों में वितरित इन्हीं केंद्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 1लाख 50हजार शिक्षित ग्रामीण युवाओं को सरकारी क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर ही स्थायी शासकीय रोजगार देने की व्यवस्था भी अंतिम चरणों में है।

25 अक्टूबर 2022 को आयोजित होने वाली अर्हता परीक्षा के उपरांत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्धता की अभूतपूर्व लहर पैदा करेगा जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों का सक्रिय और निर्णायक योगदान सुनिश्चित होगा और रोजगार के लिये शहरी क्षेत्रों की निर्भरता भी कम होगी।

संस्थान की आधिकारिक सूचना के अनुसार योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद की योजना को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी जनपदों में कृषि तथा ग्रामीण उत्पादों के उत्पादन, संग्रह, विपणन तथा विक्रय केंद्रों की ढाँचागत अवस्थापना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को उनके क्षेत्र में ही

❐ केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की योजना बदलेगी उत्तर प्रदेश के गाँवों की तकदीर

स्थायी रोजगार मिलेगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से युवा प्रतिभाओं के पलायन पर प्रभावी रोक लगेगी।

निदेशक सीबी पाँडेय के अनुसार संस्थान की सेवाओं में भर्ती के लिये आगामी 25 अक्टूबर को होने वाली अर्हता परीक्षाओं के अलावा चयन प्रक्रिया को भी पूर्णतः भ्रष्टाचारमुक्त रखना केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की नीति है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम और ईमानदार अधिकारियों के सहयोग से पूरा किया जा चुका है और इस प्रकार आगामी वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक विकास की योजना का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रगति के साथ ही राज्य के हजारों शिक्षित युवाओं को सरकारी क्षेत्र में स्थायी रोजगार देने का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया जायेगा।

कृषि विकास संस्थान की योजना बदलेगी यूपी के गांवों की तकदीर

लखनऊ, 18 अक्टूबर (तरुणमित्र)। औषधीय कृषि उत्पादों से लेकर दुग्ध उत्पादन तथा पारंपरिक कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों तक पहुंचाने के लिये जिस एकीकृत कार्ययोजना की प्रतीक्षा आजादी के बाद से ही की जा रही उसका प्रारूप अब उत्तर प्रदेश में व्यावहारिक धरातल पर दिखाई देगा। राज्य के लाखों शिक्षित ग्रामीण युवाओं को सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने के लिये केंद्रीय कृषि विकास संस्थान ने जो ढाँचागत योजना तैयार की है उसे योगी सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है।

इसके साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों शिक्षित ग्रामीण युवाओं को सरकारी क्षेत्र में स्थायी रोजगार गारंटी देने की अभूतपूर्व योजना का भी शुभारंभ हो गया है। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के निदेशक सीबी पाँडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी के दिशानिर्देशन में तैयार इस योजना के माध्यम से पूरे देश के 3 करोड़ 50 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किये जाने का दूरगामी लक्ष्य है जिसे 2028-29 के वित्तीय वर्ष तक पूरा कर लिया जाना निर्धारित है।

इसी कार्ययोजना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 8169 कार्यनिष्पादन केंद्रों की अवस्थापना गत वित्तीय वर्ष 2021-22 तक पूरी कर ली गयी है और अब राज्य के 75 जिलों में वितरित इन्हीं केंद्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 1लाख 50 हजार शिक्षित ग्रामीण युवाओं को सरकारी क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर ही स्थायी शासकीय रोजगार देने की व्यवस्था भी अंतिम चरणों में है।

25 अक्टूबर 2022 को आयोजित होने वाली अर्हता परीक्षा के उपरांत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्धता की अभूतपूर्व लहर पैदा करेगा जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों का सक्रिय और निर्णायक योगदान सुनिश्चित होगा और रोजगार के लिये शहरी क्षेत्रों की निर्भरता भी कम होगी। संस्थान की आधिकारिक सूचना के अनुसार योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद की योजना को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी जनपदों में कृषि तथा ग्रामीण उत्पादों के उत्पादन, संग्रह, विपणन तथा विक्रय केंद्रों की ढाँचागत अवस्थापना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को उनके क्षेत्र में ही स्थायी रोजगार मिलेगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से युवा प्रतिभाओं के पलायन पर प्रभावी रोक लगेगी।

निदेशक सीबी पाँडेय के अनुसार संस्थान की सेवाओं में भर्ती के लिये आगामी 25 अक्टूबर को होने वाली अर्हता परीक्षाओं के अलावा चयन प्रक्रिया को भी पूर्णतः भ्रष्टाचारमुक्त रखना केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की नीति है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम और ईमानदार अधिकारियों के सहयोग से पूरा किया जा चुका है और इस प्रकार आगामी वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक विकास की योजना का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रगति के साथ ही राज्य के हजारों शिक्षित युवाओं को सरकारी क्षेत्र में स्थायी रोजगार देने का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया जायेगा।

नशामुक्त समाज के निर्माण में मिल रहा सभी वर्गों का भरपूर सहयोग: कौशल

बीकेटी, लखनऊ, 18 अक्टूबर(तरुणमित्र)। चंद्रिका देवी मार्ग स्थित जीसीआरजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के प्रांगण में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर की अध्यक्षता में नशामुक्त समाज आंदोलन के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर ने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पर नई पीढ़ी के लोगों को नशा छोड़ो, नशे से दूर रहो, देश नशा मुक्त हो। इसके लिए नशा मुक्त समाज में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान के सभी वर्ग के लोगों में डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर, छात्र छात्राओं, महिलाओं, व्यापारियों सहित जनप्रतिनिधियों को भी इस आंदोलन से जुड़कर नशा मुक्त समाज बनाने और देश को बचाने का संकल्प लिया है।

राज्यमंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड सहित कई अन्य प्रदेशों के अंतर्गत कई जनपदों, स्कूलों में और गांव में अपने जीवन में नशा न करने का संकल्प लेते हुए संकल्पकर्ताओं ने नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का से जोड़कर नशामुक्त समाज बनाने का निश्चय किया। इस अवसर पर कॉलेज में अध्ययनरत लगभग दो हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को किसी प्रकार का नशा न करने की शपथ दिलवाई गई। उन्होंने यह भी बताया कि नशा समाज के यह अभिशाप है, और कलंक भी है इससे मानव जीवन नष्ट हो जाता है और आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। इसलिए लोगों को किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए।

ताधारी पार्टी का लाभ पहुंचाने का सकते हैं।

कि नेताजी उनके पिता के समान पूरा करने के लिए शिवपाल यादव

मुख्यमंत्री के कुशल दिशानिर्देशन में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के ढाँचागत विकास की तैयारी

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की योजना बदलेगी उत्तर प्रदेश के गाँवों की तकदीर

नुमाइंदा अपना अखबार

लखनऊ,19 अक्टूबर। औषधीय कृषि उत्पादों से लेकर दुग्ध उत्पादन तथा पारंपरिक कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों तक पहुंचाने के लिये जिस एकीकृत कार्ययोजना की प्रतीक्षा आजादी के बाद से ही की जा रही उसका प्रारूप अब उत्तर प्रदेश में व्यावहारिक धरातल पर दिखाई देगा। राज्य के लाखों शिक्षित ग्रामीण युवाओं को सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने के लिये केंद्रीय कृषि विकास संस्थान ने जो ढाँचागत योजना तैयार की है उसे योगी सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है।इसके साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों शिक्षित ग्रामीण युवाओं को सरकारी क्षेत्र मे स्थायी रोजगार गारंटी देने की अभूतपूर्व योजना का भी शुभारंभ हो गया है।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के निदेशक सीबी पाँडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशानिर्देशन मे तैयार इस योजना के माध्यम से पूरे देश के 3 करोड़ 50लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किये जाने का दूरगामी लक्ष्य है जिसे 2028-29 के वित्तीय वर्ष तक पूरा कर लिया जाना निर्धारित है।इसी कार्ययोजना के प्रथम चरण मे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 8169 कार्यनिष्पादन केंद्रों की अवस्थापना गत वित्तीय वर्ष 2021-22 तक पूरी कर ली गयी है और अब राज्य के 75जिलों मे वितरित इन्हीं केंद्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 1लाख 50हजार शिक्षित ग्रामीण युवाओं को सरकारी क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर ही स्थायी शासकीय रोजगार देने की व्यवस्था भी अंतिम चरणों में है।

25 अक्टूबर 2022 को आयोजित होने वाली अर्हता परीक्षा के उपरांत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों मे रोजगार उपलब्धता की अभूतपूर्व लहर पैदा करेगा जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मे ग्रामीण क्षेत्रों का सक्रिय और निर्णायक योगदान सुनिश्चित होगा और रोजगार के लिये शहरी क्षेत्रों की निर्भरता भी कम होगी।

संस्थान की आधिकारिक सूचना के अनुसार योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद की योजना को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी जनपदों मे कृषि तथा ग्रामीण उत्पादों के उत्पादन, संग्रह, विपणन तथा विक्रय केंद्रों की ढाँचागत अवस्थापना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को उनके क्षेत्र में ही स्थायी रोजगार मिलेगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से युवा प्रतिभाओ के पलायन पर प्रभावी रोक लगेगी।

निदेशक सीबी पाँडेय के अनुसार संस्थान की सेवाओं में भर्ती के लिये आगामी 25 अक्टूबर को होने वाली अर्हता परीक्षाओं के अलावा चयन प्रक्रिया को भी पूर्णतः भ्रष्टाचारमुक्त रखना केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की नीति है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम और ईमानदार अधिकारियों के सहयोग से पूरा किया जा चुका है और इस प्रकार आगामी वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक विकास की योजना का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रगति के साथ ही राज्य के हजारों शिक्षित युवाओं को सरकारी क्षेत्र में स्थायी रोजगार देने का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया जायेगा।

प्रज्वलन के साथ राष्ट्रगान के साथ हुई लाभार्थी दिव्यांगजन लखनऊ साथ सीतापुर हरदोई गोंडा बाराबंकी व अन्य जिलों से आए थे।

केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान की योजना बदलेगी प्रदेश के गांवों की तकदीर

स्वतंत्रभारत संवाददाता, लखनऊ। औषधीय कृषि उत्पादों से लेकर दुग्ध उत्पादन तथा पारंपरिक कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों तक पहुंचाने के लिये जिस एकीकृत कार्ययोजना की प्रतीक्षा आजादी के बाद से ही की जा रही उसका प्रारूप अब उत्तर प्रदेश में व्यावहारिक धरातल पर दिखाई देगा। राज्य के लाखों शिक्षित ग्रामीण युवाओं को सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने के लिये केंद्रीय कृषि विकास संस्थान ने जो ढाँचागत योजना तैयार की है उसे योगी सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है।इसके साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों शिक्षित ग्रामीण युवाओं को सरकारी क्षेत्र में स्थायी रोजगार गारंटी देने की अभूतपूर्व योजना का भी शुभारंभ हो गया है।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के निदेशक सीबी पाँडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशानिर्देशन में तैयार इस योजना के माध्यम से पूरे देश के 3 करोड़ 50लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किये जाने का दूरगामी लक्ष्य है ।

1974 से प्रकाशित राष्ट्रीय हिन्दी समाचार पत्र

TV लोक-लाज NEWS
You tube channel

लोक लाज

खबर वही जो बिना भय के आप तक पहुंचे।

UPHIN:26593/74

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा

19/9/2022, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

loklaj66@gmail.com

मुख्यमंत्री योगी के कुशल दिशानिर्देशन में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के ढाँचागत विकास की तैयारी

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की योजना बदलेगी उत्तर प्रदेश के गाँवों की तकदीर

लखनऊ,19अक्टूबर। औषधीय कृषि उत्पादों से लेकर दुग्ध उत्पादन तथा पारंपरिक कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों तक पहुंचाने के लिये जिस एकीकृत कार्ययोजना की प्रतीक्षा आजादी के बाद से ही की जा रही उसका प्रारूप अब उत्तर प्रदेश में व्यावहारिक धरातल पर दिखाई देगा। राज्य के लाखों शिक्षित ग्रामीण युवाओं को सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने के लिये केंद्रीय कृषि विकास संस्थान ने जो ढाँचागत योजना तैयार की है उसे योगी सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है।इसके साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों शिक्षित ग्रामीण युवाओं को सरकारी क्षेत्र में स्थायी रोजगार गारंटी देने की अभूतपूर्व योजना का भी शुभारंभ हो गया है। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के निदेशक सीबी पाँडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशानिर्देशन में तैयार इस योजना के माध्यम से पूरे देश के 3 करोड़ 50लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किये जाने का दूरगामी लक्ष्य है जिसे 2028-29 के वित्तीय वर्ष तक पूरा कर लिया जाना निर्धारित है।इसी कार्ययोजना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 8169 कार्यनिष्पादन केंद्रों की अवस्थापना गत वित्तीय वर्ष 2021-22 तक पूरी कर ली गयी है और अब राज्य के 75जिलों में वितरित इन्हीं केंद्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 1लाख 50हजार शिक्षित ग्रामीण युवाओं को सरकारी क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर ही स्थायी शासकीय रोजगार देने की व्यवस्था भी अंतिम चरणों में है। 25 अक्टूबर 2022 को आयोजित होने वाली अर्हता परीक्षा के उपरांत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्धता की अभूतपूर्व लहर पैदा करेगा जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों का सक्रिय और निर्णायक योगदान सुनिश्चित होगा और रोजगार के लिये शहरी क्षेत्रों की निर्भरता भी कम होगी। संस्थान की आधिकारिक सूचना के अनुसार योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद की योजना को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी जनपदों में कृषि तथा ग्रामीण उत्पादों के उत्पादन, संग्रह, विपणन तथा विक्रय केंद्रों की ढाँचागत अवस्थापना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को उनके क्षेत्र में ही स्थायी रोजगार मिलेगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से युवा प्रतिभाओं के पलायन पर प्रभावी रोक लगेगी। निदेशक सीबी पाँडेय के अनुसार संस्थान की सेवाओं में भर्ती के लिये आगामी 25 अक्टूबर को होने वाली अर्हता परीक्षाओं के अलावा चयन प्रक्रिया को भी पूर्णतः भ्रष्टाचारमुक्त रखना केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की नीति है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम और ईमानदार अधिकारियों के सहयोग से पूरा किया जा चुका है और इस प्रकार आगामी वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक विकास की योजना का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रगति के साथ ही राज्य के हजारों शिक्षित युवाओं को सरकारी क्षेत्र में स्थायी रोजगार देने का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया जायेगा।